NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Millennium Post, Delhi, 03/08/2026

Page No: 3, Size: 28.92cm × 13.78cm

Govt notifies prisoner death relief scheme for kin

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Kin of prison inmates who die there under unnatural circumstances will be eligible for compensation up to Rs 7.5 lakh under a scheme notified by the Delhi government.

The compensation will be paid to the next of kin or the legal heirs of prisoners who suffer unnatural death while in custody in city jails.

Under the scheme, a sum between Rs 5 lakh and Rs 7.5 lakh will be provided depending on the circumstances of each case, the Chief Minister's Office said in a statement.

According to the notification, Rs 7.5 lakh will be paid to the family of a prisoner in cases where the death occurred due to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison authorities.

A compensation of Rs 5 lakh has been prescribed in cases involving negligence by prison authorities or staff, negligence by medical or paramedical personnel, or suicide by a prisoner.

Chief Minister Rekha Gupta said the scheme, notified in accordance with the guidelines of the National Human Rights Commission (NHRC), will ensure timely relief to affected families in specified cases and will strengthen administrative accountability. According to the notification issued by the Home Department of the Delhi government, the Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025, will apply only to cases involving the unnatural death of a prisoner in any Delhi prison on or after the date of notification.

The notification stipulates that no compensation will be payable in cases of natural death or death caused by illness. Deaths occurring while escaping from prison or from lawful custody, as well as deaths caused by disasters or calamities, will not be covered under the scheme. The jail superintendent will be required to submit the magisterial inquiry report, post-mortem report, final cause of death, the prisoner's medical history, and details of the treatment provided before death to the Director General (Prisons), Delhi, in every case.

These cases will be reviewed by a committee headed by the Director General (Prisons), with the Assistant Inspector General (Prisons), the Resident Medical Officer, the Deputy Controller (Accounts), and the Law Officer as its members.

HIGHLIGHTS

- The compensation will be paid to the next of kin or the legal heirs of prisoners who suffer unnatural death while in custody in city jails
- Under the scheme, a sum between Rs 5 lakh and Rs 7.5 lakh will be provided depending on the circumstances...
- According to the notification, Rs 7.5 lakh will be paid to the family of a prisoner in cases where the death occurred due to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison authorities
- A compensation of Rs 5 lakh has been prescribed in cases involving negligence by prison authorities or staff, negligence by medical or paramedical personnel, or suicide by a prisoner

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Times of India, Delhi, 03/08/2026

Page No: 4, Size: 14.82cm × 16.80cm

Unnatural prison deaths: Kin to get compensation

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi govt has notified a compensation scheme for the next of kin or legal heirs of prisoners who suffer an unnatural death while in custody in Delhi prisons.

Compensation ranging from Rs 5 lakh to Rs 7.5 lakh will be provided depending on the circumstances of each case. Chief minister Rekha Gupta said the scheme, notified in accordance with the guidelines of National Human Rights Commission (NHRC), will ensure timely relief to the affected families.

According to the notification by Delhi govt's home (general) department, the scheme will be implemented as the Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025. It will apply only to cases involving an unnatural death of a prisoner in any Delhi prison on or after the date of notification of the scheme.

Compensation of Rs 7.5 lakh will be paid to the family of a deceased prisoner in cases where death occurs due to clashes among inmates or alleged torture or assault by prison personnel. A compensation of Rs 5 lakh will be given in cases involving negligence by prison authorities, negligence by medical or paramedical personnel, or death by suicide.

The notification makes it clear that no compensation will be payable in cases of natural death or death caused by illness.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Savera, Delhi, 03/08/2026

Page No: 1, Size: 23.81cm × 15.95cm

दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मिलेगा 7.5 लाख रुपए तक मुआवजा: सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध

सवेरा न्यूज

नई दिल्ली, 2 अगस्त : दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन अथवा वैधानिक उत्तराधिकारियों को ■ शेष पृष्ठ 4 पर

सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु अत्यंत गंभीर विषय है और ऐसे मामलों मे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन मे पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को मजबूत करना तथा प्रत्येक मामले मे विधि के अनुरूप न्याय सुनिश्चित करना है।

– मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

इन मामलों में मुआवजा देय नहीं

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु अथवा बीमारी से हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा देय नहीं होगा। इसके अलावा जेल से फरार होने अथवा वैध अभिरक्षा (हिरासत) से भागने के दौरान हुई मृत्यु और आपदा या विपदा के कारण हुई मृत्यु भी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी। योजना के तहत संबंधित जेल अधीक्षक को प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, कैदी के चिकित्सा इतिहास तथा मृत्यु से पूर्व उपलब्ध कराए गए उपचार का विवरण महानिदेशक (कारागार) दिल्ली को भेजना होगा। अधिसूचना के अनुसार महानिदेशक (कारागार) की अध्यक्षता में गठित समिति इन मामलों की समीक्षा करेगी। समिति में सहायक महानिरीक्षक (कारागार), रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, उप नियंत्रक (लेखा) तथा विधि अधिकारी भी सदस्य होंगे। समिति की अनुशंसा के आधार पर विभाग के प्रशासनिक सचिव के समक्ष मुआवजा स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने के बाद संबंधित जेल अधीक्षक इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को देंगे।

दिल्ली की जेलों में ....

मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत करेगी। दिल्ली सरकार के गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 'दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना 2025' (स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रिजनर्स इन दिल्ली प्रिजन 2025) के नाम से लागू होगी। योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी, जिनमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि अथवा उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा अथवा पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में 5 लाख रुपए का मआवजा निर्धारित किया गया है।

DJ Rashtriya Sanskaran, Delhi, 03/08/2026
Page No: 2, Size: 22.49cm × 29.90cm

जेल में अप्राकृतिक मौत पर अब 7.5 लाख रुपये तक मिलेगा मुआवजा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक कैदियों के स्वजन को आर्थिक सहायता देने के लिए नई मुआवजा योजना अधिसूचित कर दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर पांच लाख से 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।

हालांकि प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मौत को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु गंभीर विषय है। सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही व संवेदनशीलता को मजबूत करते हुए प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, कैदियों के बीच हिंसक झड़प या जेल कर्मियों द्वारा कथित मारपीट या

▸ दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की नई योजना, प्राकृतिक मृत्यु के मामलों को रखा बाहर

प्रतीकात्मक

यातना के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम स्वजन या वैधानिक उत्तराधिकारी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। वहीं, जेल अधिकारियों, चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मियों की लापरवाही अथवा कैदी द्वारा आत्महत्या में पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक मामले में जेल अधीक्षक को मजिस्ट्रियल जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु का कारण, चिकित्सा इतिहास और उपचार संबंधी विवरण महानिदेशक (कारागार) को भेजना होगा।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Punjab Kesari, Delhi, 03/08/2026

Page No: 4, Size: 9.95cm × 14.34cm

जेलों में अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा 7.5 लाख तक मुआवजा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली सरकार ने जेलों में कस्टडी के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दिशा-निर्देशों के तहत तैयार इस 'मुआवजा योजना 2025' का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को समयबद्ध आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबदेही तय करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, सरकार मानवीय गरिमा की रक्षा और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार के गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 'दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025' (स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रिजनर्स इन दिल्ली प्रिजन, 2025) के नाम से लागू होगी। योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी, जिनमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि अथवा उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा अथवा पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में 5 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है।

दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मौत पर सरकार परिवार को देगी 7.5 लाख रुपये मुआवजा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। योजना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। इसका उद्देश्य कस्टोडियल मौत के मामलों में पीड़ित परिवारों को समय रहते राहत देने के साथ जेल प्रशासन की जवाबदेही तय करना है।

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, जेल के भीतर कैदियों के बीच झगड़े या जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना अथवा मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजन या वैधानिक उत्तराधिकारी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। ब्यूरो

इन मामलों में नहीं मिलेगा लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मौत पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जेल से फरार होने या वैध अभिरक्षा से भागने के दौरान हुई मृत्यु व किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य विपदा के कारण हुई मौत भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेगी। इससे योजना का दायरा केवल अप्राकृतिक और कस्टोडियल मौतों तक सीमित रहेगा।

जांच के बाद होगा भुगतान

हर मामले में संबंधित जेल अधीक्षक को मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, चिकित्सा इतिहास और उपचार संबंधी पूरा रिकॉर्ड महानिदेशक कारागार को भेजना होगा। महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में गठित समिति इन दस्तावेजों की समीक्षा करेगी। समिति की सिफारिश के बाद प्रशासनिक सचिव के समक्ष मुआवजा स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा जाएगा। भुगतान होने के बाद इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दी जाएगी।

जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मिलेगा 7.5 लाख तक मुआवजा

भास्कर न्यूज|नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मृतक कैदियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए 'दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025' अधिसूचित की है। इसके तहत परिस्थितियों के आधार पर 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की मुआवजा राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनी यह योजना पीड़ित परिवारों को समयबद्ध राहत देने और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने में मदद करेगी। यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि या उसके बाद हुई अप्राकृतिक मौतों पर लागू होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, आपदा, या जेल से भागने/हिरासत से फरार होने के दौरान हुई मौत पर कोई मुआवजा देय नहीं होगा। मामले की जांच के लिए जेल अधीक्षक द्वारा मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल इतिहास महानिदेशक (कारागार) को सौंपा जाएगा।

मुआवजे की समीक्षा महानिदेशक (कारागार) की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी, जिसमें AIG, RMO, उप नियंत्रक (लेखा) और विधि अधिकारी शामिल होंगे।

किसे-कितना मिलेगा मुआवजा

7.5 लाख रुपए: कैदियों के बीच आपसी झगड़े या जेल कर्मियों द्वारा यातना/मारपीट के कारण हुई मौत पर।

5 लाख रुपए: जेल कर्मियों की लापरवाही, मेडिकल लापरवाही या कैदी द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Jagran, Delhi, 03/08/2026

Page No: 3, Size: 8.86cm × 12.44cm

जेल में अप्राकृतिक मौत पर अब 7.5 लाख तक मुआवजा

- दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की नई योजना, प्राकृतिक मृत्यु के मामलों को रखा बाहर
- सीएम ने कहा, अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु अत्यंत गंभीर विषय

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक कैदियों के स्वजन को आर्थिक सहायता देने के लिए नई मुआवजा योजना अधिसूचित कर दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर पांच लाख से 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मौत को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु अत्यंत गंभीर विषय है। सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को मजबूत करते हुए प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है। गृह विभाग के अनुसार, कैदियों के बीच हिंसक झड़प या जेल कर्मियों द्वारा कथित मारपीट या यातना के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम स्वजन या वैधानिक उत्तराधिकारी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। वहीं, जेल अधिकारियों, चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मियों की लापरवाही अथवा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Navbharat Times, Delhi, 03/08/2026

Page No: 5, Size: 27.09cm × 10.95cm

जेल में अप्राकृतिक मौत पर ₹7.5 लाख मुआवज़ा

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में हिरासत के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामलों में कैदी के निकटतम परिजन या कानूनी वारिस को मुआवजा देने की योजना लागू कर दी है। योजना के तहत परिस्थितियों के आधार पर 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना एनएचआरसी के दिशानिर्देशों के हिसाब से बनाई गई है। उनका कहना है कि सरकार का मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है।

File Photo

यह योजना केवल उन मामलों में लागू होगी, जिनमें अधिसूचना की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी जेल में कैदी की अप्राकृतिक मौत हुई हो। कैदियों के बीच झगड़े या जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना अथवा मारपीट से मौत होने पर 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, मेडिकल या पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही व आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

प्राकृतिक मौत या बीमारी से हुई मौत पर इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। किसी आपदा से हुई मौत भी योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी।

कैसे मिलेगी मंजूरी

जेल अधीक्षक हर मामले में मैजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मौत का आखिरी कारण, कैदी की मेडिकल हिस्ट्री और मौत से पहले दिए गए इलाज का पूरा ब्यौरा महानिदेशक (कारागार) को भेजेंगे। कमिटी इन मामलों की समीक्षा करेगी। इसके बाद प्रशासनिक सचिव के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा।

Hari Bhoomi, Delhi, 03/08/2026

Page No: 3, Size: 39.50cm × 19.24cm

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की योजना

जेलों में कस्टडी के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मिलेगा 7.5 लाख तक मुआवजा : रेखा गुप्ता

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन अथवा वैधानिक उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपये से 7 लाख 50 हजार रुपये तक की मुआवजा राशि देगी।

इस बात की जानकारी रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मुआवजा देने की इस योजना अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार के गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 'दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025' (स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रिजनर्स इन दिल्ली प्रिजन, 2025) के नाम से लागू होगी। योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी, जिनमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि अथवा उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

वहीं, जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा अथवा पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में 5 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु अत्यंत गंभीर विषय है और ऐसे मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को मजबूत करना तथा प्रत्येक मामले में विधि के अनुरूप न्याय सुनिश्चित करना है।

Source: https://www.tribuneindia.com/news/delhi/kin-of-inmates-dying-unnatural-deaths-in-delhi-prisons-to-get-up-to-7-5-lakh/amp

Kin of inmates dying unnatural deaths in Delhi prisons to get up to Rs 7.5 lakh

Govt notifies scheme, excludes fatalities due to natural causes

Tribune News Service
New Delhi, Updated At : 05:27 AM Aug 03, 2026 IST

Families of prisoners who die an unnatural death in Delhi prisons will now be eligible for compensation of up to Rs 7.5 lakh, with the Delhi Government notifying a new scheme aimed at providing relief to the next of kin while fixing accountability in cases involving negligence, assault or other unnatural causes.

The compensation will be Rs 7.5 lakh in cases where a prisoner dies due to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison personnel. Families will receive Rs 5 lakh in cases involving negligence by the prison authorities or staff, negligence by medical or paramedical personnel, or suicide by a prisoner.

The scheme, notified by the Home (General) Department as the Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025, will apply to unnatural deaths occurring in any Delhi prison on or after the date of notification.

However, the scheme will not cover deaths caused by natural causes or illness. Deaths occurring while a prisoner is attempting to escape from prison or lawful custody, as well as those caused by disasters or calamities, have also been excluded from the compensation framework.

The move is in line with the guidelines of the National Human Rights Commission (NHRC), with the government saying the scheme is intended to ensure timely relief to affected families and strengthen accountability in prison administration.

The process for awarding compensation will involve a detailed review of every case. The Jail Superintendent concerned will have to submit the magisterial inquiry report, post-mortem report, final cause of death, medical history of the prisoner and details of treatment provided before death to the Director General (Prisons), Delhi.

A committee headed by the Director General (Prisons) will then examine the case. The committee will comprise the Assistant Inspector General (Prisons), Resident Medical Officer, Deputy Controller (Accounts) and Law Officer. Its recommendations will form the basis of a proposal seeking approval for compensation from the Administrative Secretary of the department.

Once the compensation is disbursed, the Jail Superintendent concerned will also be required to inform the NHRC.

Chief Minister Rekha Gupta said: “The Delhi Government remains fully committed to upholding the rule of law, human dignity and constitutional values. Any unnatural death in custody is an extremely serious matter, and it is

the government's responsibility to ensure transparency, accountability and due process in such cases."

Source: https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/delhi-govt-announces-compensation-for-unnatural-prison-deaths-rekha-gupta-7-5-lakhs-101785693324916.html

Delhi govt announces compensation for unnatural prison deaths

The move, in line with the National Human Rights Commission (NHRC) guidelines, aims to ensure timely relief to affected families.

Updated on: Aug 3, 2026, 07:21:33 IST
By Saloni Bhatia

The Delhi government has notified a compensation scheme for families of prisoners who die an unnatural death in custody, providing financial assistance of ₹5 lakh to ₹7.5 lakh, depending on the circumstances, officials said on Sunday.

The move, in line with the National Human Rights Commission (NHRC) guidelines, aims to ensure timely relief to affected families and strengthen accountability in prison administration.

According to a notification issued by the Home (General) Department, the Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025, will apply to cases of unnatural deaths in Delhi prisons on or after the date of its notification, officials said.

₹7.5 lakh to be paid
Officials said ₹7.5 lakh will be paid in cases where a prisoner dies due to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison personnel. Compensation of ₹5 lakh will be given to cases involving death by negligence by prison authorities or medical and paramedical personnel and cases of suicide.

The scheme excludes deaths due to natural causes or illness, the notification added. It will also not cover deaths occurring while escaping from prison or lawful custody or caused by disasters or calamities.

Jail superintendent will submit report
In each case, the jail superintendent will have to submit the magisterial inquiry report, post-mortem report, final cause of death, the prisoner’s medical history and details of treatment provided before death to the director general (prisons).

The cases will be examined by a committee headed by the director general (prisons), assistant inspector general (prisons), resident medical officer, deputy controller (accounts) and law officer as members. Based on their recommendation, a proposal for compensation will be sent to the administrative secretary of the department for approval. After the amount is disbursed, the jail superintendent will inform the NHRC.

Chief minister Rekha Gupta said the government remains fully committed to upholding the rule of law, human

dignity, and constitutional values. She said any unnatural death in custody is a serious matter and it is the government’s responsibility to ensure transparency, accountability, and due process in such cases.

Source: https://punjabnewsexpress.com/national/news/delhi-govt-notifies-compensation-of-up-to-rs-75-lakh-each-for-unnatural-death-of-jail-inmates-327984

Delhi govt notifies compensation of up to Rs 7.5 lakh each for unnatural death of jail inmates
IANS Aug 2, 2026 - 16:57

NEW DELHI: The Delhi government has notified a compensation scheme – with relief amounts ranging from Rs 5 lakh to Rs 7.5 lakh - for the next of kin or legal heirs of prisoners who suffer an unnatural death during custody in city prisons, said Chief Minister Rekha Gupta.

Chief Minister Rekha Gupta said the scheme, notified in accordance with the guidelines of the National Human Rights Commission (NHRC), will ensure timely relief to affected families in specified cases while further strengthening administrative accountability.

According to the notification issued by the Home (General) Department of the Delhi Government, the scheme will be implemented as the Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025, said a statement.

It will apply only to cases involving the unnatural death of a prisoner in any Delhi prison on or after the date of notification of the scheme. As per the notification, compensation of Rs 7.5 lakh will be paid to the family of a deceased prisoner in cases where death occurs due to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison personnel, it said.

A compensation of Rs 5 lakh has been prescribed in cases involving negligence by prison authorities or staff, negligence by medical or paramedical personnel, or suicide by a prisoner, it said.

The notification makes it clear that no compensation will be payable in cases of natural death or death caused by illness. It further states that deaths occurring while escaping from prison or from lawful custody, as well as deaths caused by disasters or calamities, will not be covered under the scheme, said the statement.

Under the scheme, the Jail Superintendent concerned will be required to submit the magisterial inquiry report, post-mortem report, final cause of death, the prisoner's medical history, and details of the treatment provided before death to the Director General (Prisons), Delhi, in every case, it said.

Source: https://www.latestly.com/agency-news/india-news-jharkhand-police-launch-probe-after-gangster-sujit-sinha-killed-in-encounter-during-prison-transfer-7543216.html

India News | Jharkhand Police Launch Probe After Gangster Sujit Sinha Killed in Encounter During Prison Transfer

Get latest articles and stories on India at LatestLY. Gangster Sujit Sinha was killed in a police encounter in Jharkhand's Jamtara district in the early hours of Monday while he was being transported in a prisoner van from Sahibganj Jail to Dhanbad Jail, officials said.

By ANI | Published: Aug 03, 2026 06:28 AM IST

Jamtara (Jharkhand) [India], August 3 (ANI): Jharkhand Police have launched an investigation after gangster Sujit Sinha was killed in a police encounter in Jamtara district in the early hours of Monday while being transported from Sahibganj Jail to Dhanbad Jail.

According to police, the incident took place after the prisoner transport vehicle reportedly met with an accident during the journey. An encounter followed, in which Sinha was killed.

Senior police officials reached the spot, and heavy police deployment has been made in the area. Police have also called a Forensic Science Laboratory (FSL) team, while a magistrate is overseeing the proceedings to ensure all legal and procedural requirements are followed.

Authorities said the investigation and forensic examination will help establish the complete sequence of events leading to the encounter.

Speaking to ANI, Jamtara Superintendent of Police (SP) Shambhi Kumar Singh said, "Sujit Sinha was being transferred from Sahibganj Jail to Dhanbad Jail. Reports indicate that the vehicle met with an accident during the transit, and a police encounter ensued. We are currently conducting a thorough investigation. An FSL team has been summoned, and a magistrate is present,"

Police said the investigation is being conducted in accordance with National Human Rights Commission (NHRC) guidelines and that the forensic examination of the scene will help determine the exact circumstances surrounding the encounter. "We are proceeding in strict compliance with all NHRC guidelines... a thorough search of the scene of the incident in the presence of the magistrate will help clarify the remaining aspects," the SP added.

Further details are awaited as the probe continues. (ANI)

Source: https://www.dailyexcelsior.com/jagti-over-three-decades-in-exile-a-crumbling-township-of-daily-hardships/

Home / Latest News / Jagti | Over Three Decades In 'Exile', A Crumbling Township Of Daily Hardships

Jagti | Over Three Decades In 'Exile', A Crumbling Township Of Daily Hardships
By Daily Excelsior03:19 PM Aug 02, 2026 IST

JAGTI, Aug 2: Each morning Totaram Bhat got up and looked at the small hill close to the Jagti migrant settlement, thinking it was the ridge that formed the boundary of his ancestral village in the Anantnag district of south Kashmir. He died last month, firmly convinced that he had finally returned to his home in the valley.Executive Branch

Bhat's story is not the lone one from the Jagti satellite township, which is situated 30 km from the winter capital of Jammu and Kashmir. Many residents who had lived there for nearly three decades, including Madhusudan Zutshi and Jankinath Bhat, spent their last years dealing with dementia and Alzheimer's disease, caught between the memories of their former homes and the harsh truth of their displacement.

They died after an endless wait, without ever managing to return home.

According to lawyer Vishwa Ranjan Pandita, the tragedy experienced by Kashmiri Pandits who lived in the township following their mass exodus after terrorism broke out in the Kashmir Valley between 1989 and 1990 has now developed into a long-term fight against neglect on the part of the state.

He pointed out that although the township was built around 2010 with the intention of providing safer and more dignified housing, it has in fact become a symbol of deteriorating infrastructure and unfulfilled promises.

A prominent organisation of the Kashmiri Pandits, Panun Kashmir, is at present making preparations to take legal action, citing the "failure" of various governments to maintain the housing units built for the displaced community.Jammu Kashmir Travel

Panun Kashmir Chairman Tito Ganju said that the bad condition of Jagti township and the other camps "has made the rehabilitation of the victims and survivors of the Kashmiri Hindu genocide a serious public safety issue", pointing out that the risk of a preventable disaster increases with each monsoon season.

As Ganju pointed out, the abolition of the Engineering Wing of the Relief Department has seriously affected the supervision of important projects.

"We are demanding the immediate reestablishment of the Engineering Wing, urgent repairs, and a structural safety review of all the residential blocks; if this is not done, Panun Kashmir will ask the High Court for appropriate intervention," he said.

The township includes 4,242 two-room flats distributed among 24 buildings and provides accommodation for about 5,600 families.

Each family has a unit of 495 sq ft which consists of a bedroom, a kitchen and a lobby. Even though there is serious overcrowding and families are growing, about 80 flats are still unoccupied and more than half of the 200 commercial shops in the township have never been assigned.

Locals say that the buildings are rapidly falling into disrepair -- the outer plaster is coming off while the inside walls are affected by continuous water seepage. The condition gets worse during the monsoon when the leaking roofs result in serious water accumulation inside.

The government has not kept its promises, said T K Kaul (72), a retired official from the Accountant General's office who was born in Rainawari in downtown Srinagar. "Our situation is bad since not a single one of our complaints has been dealt with over the last ten years."

"Authorities replaced the damaged doors after repeated requests, but it was poorly done and inferior material was used. The roofs leak, the buildings require urgent repair, and our block has not had drinking water for four months," he said.

It is now an ongoing ordeal for several generations. Tej Krishan Kaul (52), who is originally from Bijbehara, described the bureaucratic nightmare which left his family in a difficult situation. Having lost his brother to crossfire in Kashmir, he was then given a housing unit.

"Three years ago officials took my documents on the grounds that I had only a temporary registration," Kaul said. "I live with my wife, three children and my elderly mother, and we have no income from which to draw. I have asked for assistance everywhere, but my appeals have been ignored."

Activists and community leaders claim that political parties have reduced the displaced community to nothing more than a political tool.

Vinod Kumar, who is known in the area as "Appu" and is a shopkeeper in the township, said: "We are being used by the political parties as a vote bank, but no actual measures are taken to rehabilitate us.

"The things that concern us every day -- such as the need for building repairs, shortages of water and unreliable electricity -- are completely ignored, and there is a strong feeling of despondency all through the township."

Sunil Pandita, a community activist from Handwara in Kupwara district who migrated in 1990, lamented, "Lord Ram's exile lasted for 14 years, whereas we have been away from our homes for 36 years and there seems to be no end to our suffering."

Pandita pointed out that although the United Progressive Alliance (UPA) government had started the housing project and had announced a package of 6,000 migrant jobs in 2009, there was no work under successive governments on the transit accommodation in Kashmir meant for the beneficiaries of the Prime Minister's package.Jammu Kashmir Travel

Residents alleged that their peaceful demonstrations asking for basic services such as water and electricity are also dealt with high-handedness.

Add to this the fact that government financial assistance has not kept up with inflation, they said.

At present, each registered relief recipient gets 9 kilograms of rice and a monthly cash payment of Rs 3,200 per person -- a sum which residents stress is not enough to meet basic living expenses, healthcare and education.

"Citizens turn to the government for assistance, but no single problem has recently been solved," said B J Bhat, who has resided there for nine years. "Although we are thankful to the Congress government which first provided the flats and introduced the relief measures, the present administration has entirely let us down."

Attempts to contact officials for a response did not yield result.

Reflecting the sense of despair in the community, some have now asked the National Human Rights Commission (NHRC), in a petition through their advocate Vishwa Ranjan Pandita, that it would be more humane for the government to put them to death quickly rather than have them endure such daily suffering.Executive Branch

The petition points out structural faults in housing units, persistent water seepage and unsanitary conditions, stating that these dangers have been neglected for more than five years because of the supposed lack of a specific repair budget.

It also highlights serious problems with connectivity, particularly regarding the important road linking Nagrota and Jagti, which has had "dangerous potholes for eight years".

Residents claim they have been treated unfairly, pointing out that while the roads throughout Jammu have been quickly resurfaced after the last assembly elections, their own vital link road has been ignored on the grounds of a supposed lack of funds.

The petition calls on the NHRC to take urgent action, summon the relevant officials and order immediate structural repairs to the flats and resurfacing of the Nagrota-Jagti road in order to avoid further loss of life. (Agencies)

Source: https://thecsrjournal.in/delhi-government-announces-compensation-scheme-for-unnatural-jail-deaths/

Delhi Government Announces Compensation Scheme for Unnatural Jail Deaths
Published By - Hency Thacker August 3, 2026

The Delhi government has introduced a new scheme that offers compensation to families or legal heirs of prisoners who die under unnatural circumstances in jails within the city. The financial assistance will range from Rs 5 lakh to Rs 7.5 lakh, depending on the specifics of each case. This announcement was made public through a statement issued by the Chief Minister's Office.

Chief Minister Rekha Gupta highlighted that this initiative is aligned with the guidelines set forth by the National Human Rights Commission. The primary aim is to provide timely support to grieving families and enhance accountability within the prison administration.

Criteria for Compensation Amounts

Under the scheme, a maximum compensation of Rs 7.5 lakh is designated for cases where the death results from inmate clashes, alleged torture, or assaults by prison personnel. Conversely, a compensation of Rs 5 lakh will be allotted when deaths occur due to negligence by prison staff, medical personnel, or in instances of suicide by prisoners.

The notification from the Home Department specifies that the Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025, is applicable only to unnatural deaths occurring on or after the date of the notification. Notably, compensation will not be granted for deaths attributed to natural causes or illnesses. Additionally, deaths incurred while a prisoner is attempting to escape or while under lawful custody are excluded from this scheme. This also extends to deaths resulting from disasters or calamities, which have been specifically excluded from compensation eligibility.

Review and Administrative Process

In instances of unnatural deaths, the jail superintendent is responsible for submitting several important documents for review. These include the magisterial inquiry report, the post-mortem report, the final cause of death, the prisoner's medical history, and details regarding any treatment provided prior to death. This comprehensive documentation is critical for the administrative process.

A committee led by the Director General of Prisons will oversee the review of the cases. This committee will also include the Assistant Inspector General of Prisons, the Resident Medical Officer, the Deputy Controller of Accounts, and a Law Officer. This multi-tiered approach is designed to ensure a thorough evaluation of each case of unnatural death in Delhi prisons.

The newly implemented scheme, therefore, establishes clear guidelines and compensation limits for specific scenarios of unnatural deaths among prisoners. With a defined process in place for administrative review, it aims to bring accountability and transparency to the handling of such sensitive matters within the prison system.

Source: https://www.thestatesman.com/cities/delhi-govt-notifies-prison-compensation-scheme-families-of-inmates-to-get-up-to-%E2%82%B97-5-lakh-for-unnatural-deaths-1503623576.html

Delhi govt notifies prison compensation scheme; families of inmates to get up to Rs7.5 lakh for unnatural deaths

The Delhi government has notified a compensation scheme under which the families or legal heirs of prisoners who die an unnatural death in custody will be eligible for compensation ranging from ₹5 lakh to ₹7.5 lakh, depending on the circumstances of the case, officials said on Sunday.

Statesman News Service | New Delhi | August 2, 2026 7:55 pm

The Delhi government has notified a compensation scheme under which the families or legal heirs of prisoners who die an unnatural death in custody will be eligible for compensation ranging from ₹5 lakh to ₹7.5 lakh, depending on the circumstances of the case, officials said on Sunday.

The scheme, notified by the Home (General) Department as the Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025, was initially proposed in September 2024 by the Aam Aadmi Party-led Delhi government and was sent to the Lieutenant Governor for approval.

While the proposal envisaged compensation of up to ₹7.5 lakh for families of prisoners who die unnatural deaths in custody, the scheme comes into force only after its notification by the Delhi government earlier this week, making it applicable to eligible custodial deaths occurring from the date of notification.

Under the notification, compensation of ₹7.5 lakh will be paid in cases where a prisoner's death is attributed to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison personnel. ₹5 lakh will be paid in cases involving alleged negligence by prison authorities or medical staff, or where a prisoner dies by suicide, officials said.

The scheme excludes compensation for natural deaths, deaths caused by illness, deaths during escape from prison or lawful custody, and deaths resulting from disasters or calamities.

Chief Minister Rekha Gupta said the scheme has been framed in line with the National Human Rights Commission (NHRC) guidelines and is intended to provide timely relief while improving accountability in prisons.

“Any unnatural death in custody is an extremely serious matter, and it is the government’s responsibility to ensure transparency, accountability and due process in such cases,” Gupta said in a statement. “Our objective is to strengthen transparency, sensitivity and accountability in prison administration while ensuring justice in every case in accordance with the law.”

The notification requires the Jail Superintendent to submit documents, including the magisterial inquiry report, post-mortem report, final cause of death and medical records, to the Director General (Prisons) in every eligible case.

According to the official order, claims will be examined by a committee headed by the Director General (Prisons),

with members drawn from the prison, medical, accounts and legal departments. Based on the committee's recommendations, the proposal will be sent to the department's administrative secretary for approval. Once the compensation is disbursed, the Jail Superintendent will inform the NHRC, the notification said.

Source: https://www.aninews.in/news/national/general-news/jharkhand-police-launch-probe-after-gangster-sujit-sinha-killed-in-encounter-during-prison-transfer20260803060050/

Jharkhand Police launch probe after gangster Sujit Sinha killed in encounter during prison transfer
ANI | Updated: Aug 03, 2026 06:00 IST

Jamtara (Jharkhand) [India], August 3 (ANI): Jharkhand Police have launched an investigation after gangster Sujit Sinha was killed in a police encounter in Jamtara district in the early hours of Monday while being transported from Sahibganj Jail to Dhanbad Jail.

According to police, the incident took place after the prisoner transport vehicle reportedly met with an accident during the journey. An encounter followed, in which Sinha was killed.

Senior police officials reached the spot, and heavy police deployment has been made in the area. Police have also called a Forensic Science Laboratory (FSL) team, while a magistrate is overseeing the proceedings to ensure all legal and procedural requirements are followed.

Authorities said the investigation and forensic examination will help establish the complete sequence of events leading to the encounter.

Speaking to ANI, Jamtara Superintendent of Police (SP) Shambhi Kumar Singh said, "Sujit Sinha was being transferred from Sahibganj Jail to Dhanbad Jail. Reports indicate that the vehicle met with an accident during the transit, and a police encounter ensued. We are currently conducting a thorough investigation. An FSL team has been summoned, and a magistrate is present,"

Police said the investigation is being conducted in accordance with National Human Rights Commission (NHRC) guidelines and that the forensic examination of the scene will help determine the exact circumstances surrounding the encounter. "We are proceeding in strict compliance with all NHRC guidelines.... a thorough search of the scene of the incident in the presence of the magistrate will help clarify the remaining aspects," the SP added.

Further details are awaited as the probe continues. (ANI)

Source: https://theindianawaaz.com/delhi-govt-announces-compensation-for-families-of-prisoners-dying-unnaturally-in-jail/

Delhi Govt announces compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail
Aug 2, 2026
Last Updated on August 2, 2026 9:28 pm by INDIAN AWAAZ

VINIT WAHI

The Delhi Government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Delhi Government's Home Department issued a notification in this regard today.

Under this scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded, depending on the specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide.

According to the notification, the scheme will apply only to cases involving the unnatural death of a prisoner in any Delhi prison occurring on or after the date of its notification.

Delhi Chief Minister Rekha Gupta stated that this scheme, notified in accordance with the guidelines of the National Human Rights Commission, will not only provide timely relief to the affected families under specified circumstances but also further strengthen administrative accountability. This scheme will further strengthen transparency, accountability, human dignity, and the rule of law within the prison administration.

FacebookMastodonEmailShare

Source: https://www.indiatoday.in/amp/india/story/delhi-jail-death-compensation-scheme-rs-7-5-lakh-families-ptag-2961758-2026-08-02

Delhi govt announces up to Rs 7.5 lakh compensation for unnatural jail deaths

Delhi has notified a compensation scheme for families of prisoners who die unnaturally in its jails. The move aligns with NHRC guidelines and sets a formal review process for accountability.

India Today News Desk
Newdelhi,UPDATED: Aug 2, 2026 23:27 IST

The Delhi government has notified a scheme under which the families or legal heirs of prisoners who die under unnatural circumstances in Delhi jails will be eligible for compensation of up to Rs 7.5 lakh. The compensation will be paid in cases covered under the new provisions.

According to a statement from the Chief Minister's Office, the amount will range between Rs 5 lakh and Rs 7.5 lakh depending on the circumstances of each case. Chief Minister Rekha Gupta said the scheme, notified in line with the National Human Rights Commission guidelines, will provide timely relief to affected families in specified cases and strengthen administrative accountability.

Under the notification, Rs 7.5 lakh will be paid to the family of a prisoner if the death took place due to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison authorities. A compensation of Rs 5 lakh has been fixed for cases involving negligence by prison authorities or staff, negligence by medical or paramedical personnel, or suicide by a prisoner.

The Home Department notification said the Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025, will apply only to cases of unnatural death in any Delhi prison on or after the date of notification. It also said no compensation will be paid in cases of natural death or death due to illness.

Deaths that take place while a prisoner is escaping from prison or from lawful custody will not be covered under the scheme. Deaths caused by disasters or calamities have also been kept outside its scope.

n every such case, the jail superintendent will have to submit the magisterial inquiry report, post-mortem report, final cause of death, the prisoner's medical history, and details of treatment provided before death to the Director General of Prisons, Delhi. The cases will then be reviewed by a committee headed by the Director General of Prisons, with the Assistant Inspector General of Prisons, the Resident Medical Officer, the Deputy Controller of Accounts, and the Law Officer as members. Overall, the scheme sets out compensation of Rs 5 lakh to Rs 7.5 lakh for specified cases of unnatural deaths in Delhi prisons, along with a defined process for review.

- Ends
Published By: Published On: Aug 2, 2026 23:27 IST

Source: https://www.thehansindia.com/news/cities/new-delhi/delhi-govt-notifies-prisoner-death-relief-scheme-for-kin-1104489

New Delhi Delhi govt notifies prisoner death relief scheme for kin
Created On: 3 Aug 2026 3:37 AM IST By The Hans India

According to the notification, Rs 7.5 lakh will be paid to the family of a prisoner in cases where the death occurred due to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison authorities.

New Delhi: Kin of prison inmates who die there under unnatural circumstances will be eligible for compensation up to Rs 7.5 lakh under a scheme notified by the Delhi government. The compensation will be paid to the next of kin or the legal heirs of prisoners who suffer unnatural death while in custody in city jails. Under the scheme, a sum between Rs 5 lakh and Rs 7.5 lakh will be provided depending on the circumstances of each case, the Chief Minister's Office said in a statement. According to the notification, Rs 7.5 lakh will be paid to the family of a prisoner in cases where the death occurred due to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison authorities. A compensation of Rs 5 lakh has been prescribed in cases involving negligence by prison authorities or staff, negligence by medical or paramedical personnel, or suicide by a prisoner.
Chief Minister Rekha Gupta said the scheme, notified in accordance with the guidelines of the National Human Rights Commission (NHRC), will ensure timely relief to affected families in specified cases and will strengthen administrative accountability. According to the notification issued by the Home Department of the Delhi government, the Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025, will apply only to cases involving the unnatural death of a prisoner in any Delhi prison on or after the date of notification. The notification stipulates that no compensation will be payable in cases of natural death or death caused by illness. Deaths occurring while escaping from prison or from lawful custody, as well as deaths caused by disasters or calamities, will not be covered under the scheme. The jail superintendent will be required to submit the magisterial inquiry report, post-mortem report, final cause of death, the prisoner's medical history, and details of the treatment provided before death to the Director General (Prisons), Delhi, in every case. These cases will be reviewed by a committee headed by the Director General (Prisons), with the Assistant Inspector General (Prisons), the Resident Medical Officer, the Deputy Controller (Accounts), and the Law Officer as its members.

Source: https://www.zeebiz.com/india/news-delhi-govt-announces-rs-75-lakh-compensation-for-unnatural-deaths-in-prison-custody-399783

Delhi govt announces Rs 7.5 lakh compensation for unnatural deaths in prison custody
Written By Ankit Kumar
Published: 7:53 PM, Aug 2, 2026 | Updated: 7:53 PM, Aug 2, 2026

The Delhi government has notified a compensation scheme offering up to Rs 7.5 lakh to families of prisoners who die due to unnatural causes in custody. Check eligibility, compensation amount and key details.

The Delhi government has notified a compensation scheme for the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody in prisons across the national capital. Under the new policy, families will receive financial assistance of up to Rs 7.5 lakh, depending on the circumstances surrounding the death.

The notification, issued by the Delhi Government's Home Department, will apply only to cases involving the unnatural death of a prisoner in any Delhi prison occurring on or after the date of its notification.

Delhi Chief Minister Rekha Gupta said the scheme has been notified in line with the guidelines of the National Human Rights Commission (NHRC). She said the initiative would provide timely financial relief to affected families while strengthening transparency, accountability, human dignity and the rule of law within the prison administration.

How much compensation will families receive?
Under the notified scheme, the amount of compensation will depend on the circumstances surrounding the prisoner's death.

Families will receive Rs 7.5 lakh if a prisoner dies due to conflicts among inmates or alleged assault by jail staff while in custody.

Meanwhile, Rs 5 lakh compensation has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and prisoner suicides.

However, the scheme does not cover deaths caused by natural reasons or illness.

What did CM Rekha Gupta say?
Chief Minister Rekha Gupta said the compensation scheme has been introduced in accordance with the NHRC's guidelines for custodial deaths.

According to the Chief Minister, the policy will ensure timely financial assistance to the families of deceased prisoners in specified cases while promoting greater administrative accountability.

She added that the scheme would strengthen transparency, accountability, human dignity and adherence to the rule of law in Delhi's prison administration.

Who is eligible under the scheme?
The compensation will be provided to the next of kin or legal heirs of prisoners who die due to unnatural causes while in custody in Delhi prisons.

The scheme is applicable only to cases of unnatural deaths that occur on or after the date of its notification. Deaths that took place before the notification are not covered.

The financial assistance will be released in accordance with the provisions laid down by the Delhi government's Home Department after the relevant case is examined.

FAQs
What is the Delhi prison compensation scheme?
The scheme provides financial assistance to the families or legal heirs of prisoners who die due to unnatural causes while in custody in Delhi prisons. It has been notified by the Delhi government's Home Department.

What is the maximum compensation available?
The maximum compensation under the scheme is Rs 7.5 lakh. The amount payable depends on the circumstances that led to the prisoner's death.

In which cases will Rs 7.5 lakh be paid?
Compensation of Rs 7.5 lakh will be paid if a prisoner's death is caused by conflicts among inmates or alleged assault by jail staff.

When will Rs 5 lakh compensation be provided?
Families will receive Rs 5 lakh in cases involving negligence by prison officials, negligence by medical or paramedical personnel, or if a prisoner dies by suicide while in custody.

Are natural deaths covered under the scheme?
No. The scheme specifically excludes deaths resulting from natural causes or illness. It is applicable only to cases involving unnatural deaths in prison custody.

Who can claim the compensation?
The compensation can be claimed by the next of kin or legal heirs of the deceased prisoner, subject to the conditions specified under the scheme.

When does the scheme come into effect?
The scheme applies only to cases of unnatural deaths that occur on or after the date of its official notification by the Delhi government's Home Department.

Source: https://www.bignewsnetwork.com/news/279220151/jharkhand-police-launch-probe-after-gangster-sujit-sinha-killed-in-encounter-during-prison-transfer

Jharkhand Police launch probe after gangster Sujit Sinha killed in encounter during prison transfer
ANI
3rd August 2026, 10:58 GMT+11

Jamtara (Jharkhand) [India], August 3 (ANI): Jharkhand Police have launched an investigation after gangster Sujit Sinha was killed in a police encounter in Jamtara district in the early hours of Monday while being transported from Sahibganj Jail to Dhanbad Jail.

According to police, the incident took place after the prisoner transport vehicle reportedly met with an accident during the journey. An encounter followed, in which Sinha was killed.

Senior police officials reached the spot, and heavy police deployment has been made in the area. Police have also called a Forensic Science Laboratory (FSL) team, while a magistrate is overseeing the proceedings to ensure all legal and procedural requirements are followed.

Authorities said the investigation and forensic examination will help establish the complete sequence of events leading to the encounter.

Speaking to ANI, Jamtara Superintendent of Police (SP) Shambhi Kumar Singh said, 'Sujit Sinha was being transferred from Sahibganj Jail to Dhanbad Jail. Reports indicate that the vehicle met with an accident during the transit, and a police encounter ensued. We are currently conducting a thorough investigation. An FSL team has been summoned, and a magistrate is present,'

Police said the investigation is being conducted in accordance with National Human Rights Commission (NHRC) guidelines and that the forensic examination of the scene will help determine the exact circumstances surrounding the encounter. 'We are proceeding in strict compliance with all NHRC guidelines... a thorough search of the scene of the incident in the presence of the magistrate will help clarify the remaining aspects,' the SP added.

Further details are awaited as the probe continues. (ANI)

Source: https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/delhi-notifies-compensation-scheme-for-unnatural-deaths-of-prison-inmates/article71297818.ece/amp/

Delhi notifies compensation scheme for unnatural deaths of prison inmates

Families of prison inmates who die under unnatural circumstances will be eligible for compensation of up to ₹7.5 lakh under a Delhi government scheme aligned with NHRC guidelines

Updated - August 02, 2026 07:33 pm IST - New Delhi
The Hindu Bureau

New Delhi

Family members of inmates who die in prisons in the national capital under unnatural circumstances will be eligible for compensation of up to ₹7.5 lakh under a scheme notified by the Delhi government, the Chief Minister's Office (CMO) said on Sunday (August 2, 2026).

Chief Minister Rekha Gupta said the scheme, notified in accordance with the guidelines of the National Human Rights Commission (NHRC), would ensure timely relief to affected families in specified cases while further strengthening administrative accountability.

The Scheme for Payment of Compensation on Account of Death of Prisoners in Delhi Prison, 2025, will apply only to cases involving the unnatural death of a prisoner in any Delhi prison on or after the date of its notification.

According to the notification, compensation of ₹7.5 lakh will be paid to the family of a deceased prisoner in cases where death occurs due to clashes between inmates or alleged torture or assault by prison personnel. Compensation of ₹5 lakh has been prescribed in cases involving negligence by prison authorities or staff, negligence by medical or paramedical personnel, or suicide by a prisoner.

Under the scheme, the concerned Jail Superintendent will be required to submit the magisterial inquiry report, post-mortem report, final cause of death, the prisoner's medical history, and details of the treatment provided before death to the Director General (Prisons), Delhi, in every case.

These cases will be reviewed by a committee headed by the Director General (Prisons). Based on the committee's recommendation, a proposal seeking approval for the compensation will be placed before the Administrative Secretary of the Home Department. Once the compensation has been disbursed, the concerned Jail Superintendent will inform the National Human Rights Commission.

The Chief Minister said the Delhi government was fully committed to upholding the rule of law, human dignity and constitutional values. She said any unnatural death in custody was an extremely serious matter, and it was the government's responsibility to ensure transparency, accountability and due process in such cases. "The government's objective is to strengthen transparency, sensitivity, and accountability in prison administration while ensuring justice in every case in accordance with the law," she said.

In September 2017, the Supreme Court directed the Chief Justices of all High Courts to suo motu register petitions to identify the kin of prisoners who died unnatural deaths from 2012 and direct the States to award them compensation.

Published - August 02, 2026 07:00 pm IST

Source: https://www.timesnowhindi.com/cities/jharkhand-police-encounter-gangster-sujit-sinha-dies-near-jamtara-article-155234219

जामताड़ा में पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की मौत, जेल शिफ्टिंग के दौरान हुआ हादसा
Edited by: पूजा कुमारी Updated Aug 3, 2026, 07:01 AM IST

झारखंड के जामताड़ा में साहिबगंज जेल से धनबाद जेल ले जाए जा रहे गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रास्ते में वाहन दुर्घटना के बाद मुठभेड़ हुई। मामले की जांच जारी है। एफएसएल टीम और मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद हैं तथा NHRC की गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की सोमवार तड़के जामताड़ा जिले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, उसे साहिबगंज जेल से धनबाद जेल ले जाया जा रहा था। रास्ते में कैदियों को ले जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद मुठभेड़ की घटना हुई।

हादसे के बाद हुई मुठभेड़
पुलिस के मुताबिक, जेल ट्रांसफर के दौरान वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हालात बिगड़ गए। इसके बाद पुलिस और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इस घटना में गैंगस्टर की मौत हो गई। हालांकि, मुठभेड़ किन हालातों में हुई, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी जांच के लिए घटनास्थल पर बुलाया है। जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

NHRC के दिशा-निर्देशों के तहत जांच
जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक (SP) शंभी कुमार सिंह ने बताया कि सुजीत सिन्हा को साहिबगंज जेल से धनबाद जेल ले जाया जा रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रास्ते में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसके बाद मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। FSL टीम घटनास्थल की जांच कर रही है और मजिस्ट्रेट की निगरानी में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जा रही है।

जांच रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर यह साफ हो सकेगा कि मुठभेड़ से पहले और उसके दौरान क्या घटनाक्रम हुआ। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस ने जल्द ही पूरी रिपोर्ट सामने आने की बात कही है।

Source: https://rashtriyakhabar.com/225073/

दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा 7.5 लाख तक का मुआवजा: दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की नई योजना
By Rajat Kumar Gupta On Aug 2, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विभिन्न जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन अथवा उनके वैध उत्तराधिकारियों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने हेतु एक ऐतिहासिक योजना अधिसूचित की है।

इस जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर पीड़ित परिजनों को ₹5 लाख से लेकर ₹7.5 लाख तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।

🏛️ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों पर आधारित है 'कैदी मुआवजा योजना 2025'
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित और विषम परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ-साथ जेल प्रशासन की उत्तरदायित्व क्षमता को अधिक मजबूत करेगी।

दिल्ली सरकार के गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह योजना "दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025" के नाम से लागू की जाएगी। यह व्यवस्था केवल उन्हीं मामलों पर प्रभावी होगी, जिनमें योजना की अधिसूचना तिथि या उसके उपरांत दिल्ली की किसी भी जेल में कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो।

💰 आपसी मारपीट पर ₹7.5 लाख और लापरवाही पर ₹5 लाख मुआवजा तय, प्राकृतिक मौत पर नहीं मिलेगी राशि
अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, कैदियों के आपस में झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना व मारपीट के कारण होने वाली मृत्यु पर परिजनों को ₹7.5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।

वहीं, जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की चूक अथवा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के प्रकरणों में ₹5 लाख का मुआवजा निर्धारित किया गया है।

अपवाद: प्राकृतिक मृत्यु या किसी गंभीर बीमारी से हुई मौत के मामलों में मुआवजा देय नहीं होगा। इसके अलावा, जेल से फरार होने/हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु और प्राकृतिक आपदा-विपदा के चलते हुई मौतों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

📜 महानिदेशक (कारागार) को भेजनी होगी मजिस्ट्रियल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट
योजना के सफल संचालन हेतु संबंधित जेल अधीक्षक को प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, कैदी का मेडिकल इतिहास तथा मृत्यु से पूर्व उपलब्ध कराए गए इलाज का पूरा विवरण महानिदेशक (कारागार) दिल्ली को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

🔍 डीजी जेल की अध्यक्षता में बनेगी उच्चस्तरीय समिति, जेल प्रशासन में बढ़ेगी पारदर्शिता
अधिसूचना के अनुसार, महानिदेशक (कारागार) की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समिति इन मामलों की गहन समीक्षा करेगी।

इस समिति में सहायक महानिरीक्षक (कारागार), रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, उप नियंत्रक (लेखा) तथा विधि अधिकारी बतौर सदस्य शामिल रहेंगे। समिति की अनुशंसा के आधार पर ही विभाग के प्रशासनिक सचिव के समक्ष मुआवजा स्वीकृति का अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुआवजा राशि के भुगतान के उपरांत संबंधित जेल अधीक्षक इसकी आधिकारिक सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को प्रेषित करेंगे।

⚖️ "मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है सरकार": मुख्यमंत्री का वक्तव्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका

कस्टडी के दौरान किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु होना अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विधिसम्मत

कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सरकार का मुख्य ध्येय जेल प्रशासन में संवेदनशीलता और जवाबदेही को बढ़ाना तथा प्रत्येक मामले में विधि के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है।

Dainik Bhaskar, Online News, 03/08/2026

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/75-delhi-ki-jelon-mein-aprakritik-mrityu-ke-mamlon-mein-milega-7-5-lakh-rupaye-tak-muawza-cm-rekha-gupta-1338104

दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मिलेगा 7.5 लाख रुपए तक मुआवजा सीएम रेखा गुप्ता
2 Aug 2026 4:47 PM

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन अथवा वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है।

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन अथवा वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत करेगी। दिल्ली सरकार के गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 'दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना 2025' (स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रिजनर्स इन दिल्ली प्रिजन 2025) के नाम से लागू होगी। योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी, जिनमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि अथवा उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा अथवा पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में 5 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु अथवा बीमारी से हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा देय नहीं होगा। इसके अलावा जेल से फरार होने अथवा वैध अभिरक्षा (हिरासत) से भागने के दौरान हुई मृत्यु और आपदा या विपदा के कारण हुई मृत्यु भी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी। योजना के तहत संबंधित जेल अधीक्षक को प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, कैदी के चिकित्सा इतिहास तथा मृत्यु से पूर्व उपलब्ध कराए गए उपचार का विवरण महानिदेशक (कारागार) दिल्ली को भेजना होगा। अधिसूचना के अनुसार महानिदेशक (कारागार) की अध्यक्षता में गठित समिति इन मामलों की समीक्षा करेगी। समिति में सहायक महानिरीक्षक (कारागार), रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, उप नियंत्रक (लेखा) तथा विधि अधिकारी भी सदस्य होंगे। समिति की अनुशंसा के आधार पर विभाग के प्रशासनिक सचिव के समक्ष मुआवजा स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने के बाद संबंधित जेल अधीक्षक इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को देंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु अत्यंत गंभीर विषय है और ऐसे मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को मजबूत करना तथा प्रत्येक मामले में विधि के अनुरूप न्याय सुनिश्चित करना है।

Source: https://www.haribhoomi.com/national/news/delhi-jails-unnatural-deaths-compensation-policy-7-point-5-lakh-nhrc-guidelines-106937

Delhi Jails Compensation: जेल हिरासत में मौत पर 7.5 लाख का मुआवजा; NHRC के निर्देशों पर दिल्ली सरकार का फैसला!

दिल्ली सरकार ने NHRC के दिशा-निर्देशों के तहत जेलों में होने वाली अप्राकृतिक मौतों के लिए नई मुआवजा योजना अधिसूचित की है। इसके तहत जेल में हिंसा, यातना या लापरवाही से मौत होने पर पीड़ित कैदियों के परिजनों को 5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

By: अभिषेक यादव
Published: 03 Aug 2026, 07:52 AM IST
Last Updated: 03 Aug 2026, 07:52 AM IST

दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में कैदियों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए नई मुआवजा योजना को अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के तहत लागू की गई इस नीति के माध्यम से जेल प्रशासन में जवाबदेही और संवेदनशीलता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस योजना के तहत परिस्थिति के आधार पर 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

हिंसा और यातना से मौत पर 7.5 लाख की सहायता: सीएम ने कहा- 'अभिरक्षा में अप्राकृतिक मृत्यु गंभीर विषय'
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि जेल के भीतर कैदियों के बीच आपस में हिंसक झड़प होती है, या फिर जेल कर्मचारियों द्वारा कथित मारपीट और शारीरिक यातना के कारण किसी कैदी की जान जाती है, तो मृतक के निकटतम परिजन या वैधानिक उत्तराधिकारी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु एक अत्यंत गंभीर विषय है। सरकार का मुख्य उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को मजबूत करते हुए प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है।

आत्महत्या और लापरवाही के मामलों में 5 लाख का प्रावधान, लेकिन प्राकृतिक मौत पर नहीं मिलेगा मुआवजा
योजना के दूसरे चरण में यह तय किया गया है कि यदि जेल अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों या पैरामेडिकल कर्मियों की लापरवाही के कारण किसी कैदी की मृत्यु होती है, अथवा कैदी द्वारा जेल के अंदर आत्महत्या की जाती है, तो ऐसी स्थिति में परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि, इस योजना में कड़े नियम भी शामिल किए गए हैं।

प्राकृतिक मृत्यु, किसी पुरानी बीमारी के कारण होने वाली मौत, जेल से फरार होने के दौरान हुई दुर्घटना या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मृत्यु को इस मुआवजा योजना के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

मजिस्ट्रियल जांच से लेकर NHRC को सूचना तक: जानिए मुआवजा स्वीकृति की पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया
मुआवजे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। योजना के तहत हर मामले में जेल अधीक्षक को मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के सटीक कारण, कैदी का मेडिकल इतिहास और उसके इलाज से संबंधित सभी दस्तावेज महानिदेशक को भेजने अनिवार्य होंगे।

इसके बाद महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति इन सभी रिपोर्ट्स की गहन समीक्षा करेगी और मुआवजे की स्वीकृति के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। प्रशासनिक सचिव द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने और परिजनों को भुगतान पूरा होने के बाद इसकी विस्तृत सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी साझा की जाएगी।

Source: https://dainiksaveratimes.com/punjab/human-rights-commission-inspected-the-jail/

मानवाधिकार आयोग ने पट्टी जेल का किया निरीक्षण
August 2, 2026

Human Rights Commission inspected the jail. : अमृतसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अखिल कुमार शुक्ला ने पट्टी सब-जेल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेल की कोठरियों और बैरकों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी बैरकों में हर कैदी से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।

जेल की सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण
उन्होंने बैरकों में बने बाथरूम की सफाई-व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने कैदियों की समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने जेल में बन रहे खाने का भी निरीक्षण किया, जिसमें रोटी, दाल, काले चने और खीर आदि शामिल थे। उन्होंने जेल में बनी डिस्पेंसरी, कैंटीन और लाइब्रेरी की भी जांच की। उन्होंने जेल और जेल की इमारत की सफाई-व्यवस्था को भी बारीकी से देखा। उन्होंने कैदियों से उन्हें दी जा रही मेडिकल सुविधाओं, मुफ्त कानूनी सहायता और अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली।

पुरानी जेल भवन की मरम्मत का सुझाव
उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट इंदरप्रीत सिंह से जेल के बारे में जानकारी ली कि जेल कब बनी थी और वहां क्या-क्या सुविधाएं हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जेल की इमारत पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसकी जल्द से जल्द मरम्मत कराई जानी चाहिए। इस मौके पर जेल सुपरिटेंडेंट इंदरप्रीत सिंह PPS, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सतनाम सिंह, जेल मेडिकल ऑफिसर डॉ. हरसिमरत सिंह, फार्मासिस्ट नवदीप सिंह, स्टोर कीपर जतिंदर सिंह और जेल के अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।

Source: https://www.amarujala.com/delhi-ncr/lakh-in-compensation-to-the-families-of-those-who-die-an-unnatural-death-in-delhis-jails-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-148748-2026-08-02

Delhi NCR News: दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मौत पर सरकार परिवार को देगी 7.5 लाख रुपये मुआवजे का सहारा
Amar Ujala Bureauअमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2026 06:00 PM IST

सरकार ने अधिसूचित की नई योजना, कैदियों के परिजनों को परिस्थितियों के अनुसार 5 से 7.5 लाख रुपये

प्राकृतिक मौत और बीमारी के मामलों में नहीं मिलेगा लाभ, जांच रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। योजना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई है। इसका उद्देश्य कस्टोडियल मौत के मामलों में पीड़ित परिवारों को समय रहते राहत देने के साथ जेल प्रशासन की जवाबदेही तय करना है।

गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, जेल के भीतर कैदियों के बीच झगड़े या जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना अथवा मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजन या वैधानिक उत्तराधिकारी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। वहीं जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही, चिकित्सा या पैरामेडिकल स्टाफ की लापरवाही व कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने की स्थिति में 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना अधिसूचना की तिथि या उसके बाद होने वाली घटनाओं पर ही लागू होगी।

इन मामलों में नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मौत पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जेल से फरार होने या वैध अभिरक्षा से भागने के दौरान हुई मृत्यु व किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य विपदा के कारण हुई मौत भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेगी। इससे योजना का दायरा केवल अप्राकृतिक और कस्टोडियल मौतों तक सीमित रहेगा।

जांच के बाद होगा भुगतान
हर मामले में संबंधित जेल अधीक्षक को मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, चिकित्सा इतिहास और उपचार संबंधी पूरा रिकॉर्ड महानिदेशक कारागार को भेजना होगा। महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में गठित समिति इन दस्तावेजों की समीक्षा करेगी। समिति की सिफारिश के बाद प्रशासनिक सचिव के समक्ष मुआवजा स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा जाएगा। भुगतान होने के बाद इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दी जाएगी।

Source: https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-delhi-jails-up-to-75-lakh-compensation-for-unnatural-deaths-40327521.html

दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मौत पर मिलेगा 7.5 लाख तक मुआवजा, सरकार ने अधिसूचित की नई योजना
By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
Updated: Mon, 03 Aug 2026 06:59 AM (IST)

दिल्ली सरकार ने जेलों में अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने के लिए नई मुआवजा योजना अधिसूचित की है।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई मुआवजा योजना अधिसूचित कर दी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की गई इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर पांच लाख से 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मौत को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

अप्राकृतिक मृत्यु अत्यंत गंभीर विषय
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु अत्यंत गंभीर विषय है। सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को मजबूत करते हुए प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है।

गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच हिंसक झड़प अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित मारपीट या यातना के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजन या वैधानिक उत्तराधिकारी को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

वहीं जेल अधिकारियों, चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मियों की लापरवाही अथवा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। जेल से फरार होने के दौरान या प्राकृतिक आपदा में हुई मृत्यु पर यह योजना लागू नहीं होगी।

भुगतान होने पर एनएचआरसी को भी दी जाएगी सूचना
योजना के तहत प्रत्येक मामले में जेल अधीक्षक को मजिस्ट्रियल जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु का कारण, चिकित्सा इतिहास और उपचार संबंधी विवरण महानिदेशक (कारागार) को भेजना होगा।

महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति मामले की समीक्षा कर मुआवजा स्वीकृति की संस्तुति करेगी, जिसके बाद प्रशासनिक सचिव अंतिम निर्णय लेंगे। भुगतान होने पर इसकी सूचना एनएचआरसी को भी दी जाएगी।

Source: https://www.tv9hindi.com/india/delhi-jail-prisoner-death-compensation-scheme-rekha-gupta-3869308.html

Hindi News India Delhi jail prisoner death compensation scheme rekha gupta

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, कस्टडी डेथ पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा

दिल्ली सरकार ने जेलों में कस्टडी के दौरान अप्राकृतिक मौत के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक मुआवजा देने की योजना लागू की है. यह योजना NHRC के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई है.

जीतेन्द्र भाटी | Edited By: अजय विद्यार्थी | Updated on: Aug 02, 2026 5:31 PM IST

Highlights
हर मामले में मजिस्ट्रियल जांच-पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मुआवजा स्वीकृत होगा.
मुआवजा भुगतान के बाद NHRC को अनिवार्य रूप से सूचना दी जाएगी.
नई योजना केवल अधिसूचना लागू होने के बाद होने वाली घटनाओं पर लागू होगी.

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा (कस्टडी) के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन अथवा वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है. इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की मुआवजा राशि दी जाएगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत करेगी.

दिल्ली सरकार के गृह (सामान्य) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना दिल्ली जेलों में कैदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025 (स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ कम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ प्रिजनर्स इन दिल्ली प्रिजन, 2025) के नाम से लागू होगी. योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी, जिनमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि अथवा उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो.

7.5 लाख रुपये तक मिलेगा मुआवजा
अधिसूचना के अनुसार कैदियों के बीच आपसी झगड़े अथवा जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, चिकित्सा अथवा पैरामेडिकल अधिकारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में 5 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है.

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक मृत्यु अथवा बीमारी से हुई मृत्यु के मामलों में मुआवजा देय नहीं होगा. इसके अलावा जेल से फरार होने अथवा वैध अभिरक्षा (हिरासत) से भागने के दौरान हुई मृत्यु और आपदा या विपदा के कारण हुई मृत्यु भी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी.

योजना के तहत संबंधित जेल अधीक्षक को प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु के अंतिम कारण, कैदी के चिकित्सा इतिहास तथा मृत्यु से पूर्व उपलब्ध कराए गए उपचार का विवरण महानिदेशक (कारागार) दिल्ली को भेजना होगा.

जेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर
अधिसूचना के अनुसार महानिदेशक (कारागार) की अध्यक्षता में गठित समिति इन मामलों की समीक्षा करेगी. समिति में सहायक महानिरीक्षक (कारागार), रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, उप नियंत्रक (लेखा) तथा विधि अधिकारी भी सदस्य होंगे. समिति की अनुशंसा के आधार पर विभाग के प्रशासनिक सचिव के समक्ष मुआवजा स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा जाएगा. अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि मुआवजा राशि का भुगतान किए जाने के बाद संबंधित जेल अधीक्षक इसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को देंगे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार कानून के शासन, मानवीय गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मृत्यु अत्यंत गंभीर विषय है और ऐसे मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को मजबूत करना तथा प्रत्येक मामले में विधि के अनुरूप न्याय सुनिश्चित करना है.

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-aligarh-industry-body-complains-to-nhrc-over-unjust-water-tax-bills-201785691432267.amp.html

जल मूल्य एवं जलकर लगाने के विरोध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत
Aug 02, 2026 10:53 pm IST
By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़

अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नगर निगम द्वारा बिना तैयारी के जल कर और जल मूल्य बिल थोपने की शिकायत की है। व्यापारियों को पानी का कनेक्शन नहीं मिलने के बावजूद उन पर बिल लगाए गए हैं, जिससे नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता हाउस टैक्स के बिल में जलकर व जल मूल्य लगाने पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की है। आरोप है कि नगर निगम ने बिना तैयारी के उपभोक्ताओं पर बिल थोप दिया। जबकि व्यापारियों समेत उपभोक्ताओं के पास पानी का कनेक्शन नहीं है।उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक समर्पण कॉम्प्लेक्स रेलवे रोड पर हुई। जिसमें महानगर सतीश महेश्वरी ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी अपनी तानाशाही पर अडिग हैं। शिकायत राष्ट्रीय मानवाअधिकार आयोग के अध्यक्ष से की गई है। किशन गुप्ता कोषाध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम के अभिलेखों में इस बात को कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि उसने कितने पानी के कनेक्शन दिए हैं।

अभिलेखों की कमी पूरा करने को लाखों नागरिकों व व्यापारियों को संकट में डाल दिया है। अपने की सही सिद्ध करने के लिए नगर निगम में घंटों इंतजार कर आपत्ति लगा रहे हैं, जिसका निस्तारण 20-25 दिन में भी नहीं हो रहा। अधिकारी और कर्मचारी गलत कर आरोपण से परेशान हैं। घनश्याम दास जैन महामंत्री ने कहा कि जब 200 मीटर की परिधि में कोई पानी का कोई स्रोत ही नहीं है तो उपभोक्ता और जल कर कैसे आरोपित कर दिया। संजय वार्ष्णेय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि गंभीर पक्ष यह भी है कि अनेक नागरिकों द्वारा जून माह में ही बिल जमा कर दिए और भुगतान के बाद नगर निगम ने लाखों बिल संशोधित कर दिए और अब आपत्ति लगानी पड़ रही हैं। नागरिकों के मानवाधिकारों को हनन करने का मामला बनता है। व्यापार मंडल ने आयोग मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर हनुमंतराम गांधी, दीपक कोरल, नवीन राठी, दाऊदयाल गुप्ता, पंकज गुप्ता, अनुपम वार्ष्णेय, संयोग मित्तल, करण मित्तल, संदीप मित्तल, प्रशांत मित्तल, विकास शर्मा , गर्वित महेश्वरी मौजूद रहे।

Source: https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-rekha-gupta-govt-notifies-prisoner-death-relief-scheme-for-kin-under-unnatural-circumstances-compensation-up-to-rs-7-5-lakh-3169389/amp

दिल्ली सरकार की योजना, कैदियों की मौत पर परिजनों को मुआवजा

एबीपी स्टेट डेस्क

| 02 Aug 2026 08:12 PM (IST)

Delhi News: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की योजना के मुताबिक जेलों में अस्वाभाविक परिस्थितियों में कैदियों की मौत होने पर उनके परिजनों को साढ़े सात लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा.

दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार कैदियों से जुड़ी एक बड़ी योजना लेकर आ रही है. इस स्कीम के तहत जेल में अस्वाभाविक परिस्थितियों में कैदियों की मौत होने पर उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा. जान गंवाने वाले कैदियों के परिजनों को अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी. हालांकि किसी बीमारी से मौत पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा.

दिल्ली सीएमओ की ओर से इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस के एक्स हैंडल पर लिखा गया, ''साढ़े सात लाख तक का मुआवजा अब दिल्ली की जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृतक बंदियों के परिजनों को दिया जाएगा. प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मौत इस योजना के दायरे में नहीं होगी.''

किन परिस्थितियों में मौत पर कितना मुआवजा?

इस योजना के मुताबिक कैदियों के बीच संघर्ष या जेल कर्मियों द्वारा कथित मारपीट से मौत होने पर 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, लापरवाही या सुसाइड के मामलों में 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. सरकार का मानना है कि यह योजना जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और मजबूत करेगी.

NHRC के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीड़ित परिवारों को मिलेगी राहत

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना निर्धारित मामलों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सुनिश्चित करेगी. इसके साथ ही इस सरकार की इस अहम योजना के जरिए प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूती मिलेगी.

सिर्फ अस्वाभाविक मौत के मामलों पर ही लागू होगी योजना

दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली की जेलों में कैदियों की मौत पर मुआवजा भुगतान योजना, 2025' अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में कैदी की अस्वाभाविक मौत के मामलों पर ही लागू होगी.

Published at: 02 Aug 2026 08:12 PM (IST)

Tags: Rekha Gupta DELHI NEWS